



हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

44 मंत्रालय — हर कार्ड पर मंत्रालय का हस्ताक्षर

- इस PDF का हर पृष्ठ एक पोस्ट-कार्ड है — किसी भी पृष्ठ का स्क्रीनशॉट लीजिए और WhatsApp, X, Facebook, Instagram या किसी भी ऐप पर साझा कीजिए।
- हर कार्ड पर आँकड़े की तिथि है; पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर।

गुजरात · मुख्यमंत्री

भारत · प्रधानमंत्री

2001

2014

2026

PIntelligence · संस्करण 88 · 7 अक्टूबर 2026

#25YearsofSeva

25YearsofSeva.com

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

गृह मंत्रालय

अनुच्छेद 370 से नक्सल-मुक्त भारत तक

- 1 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ; 11 दिसम्बर 2023 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस निर्णय की वैधता पुष्ट की।
- 2 1 जुलाई 2024 से तीन नई न्याय संहिताएँ लागू हुईं, जिन्होंने 1860 की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।
- 3 30 मार्च 2026 को लोकसभा में नक्सल-मुक्त भारत की घोषणा हुई: नक्सल-प्रभावित जिले अप्रैल 2024 के 38 से घटकर 31 मार्च 2026 को शून्य रह गए।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय

ऑपरेशन सिंदूर, INS विक्रान्त, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात



- 1 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके के नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई हुई; इससे पहले 29 सितम्बर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 26 फरवरी 2019 की बालाकोट कार्रवाई ने सीमा पार आतंक के विरुद्ध नई नीति की रेखा खींची थी।
- 2 2 सितम्बर 2022 को पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रान्त नौसेना में शामिल हुआ और उसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नया नौसेना ध्वज अपनाया गया।
- 3 रक्षा निर्यात 2013-14 के ₹686 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹38,424 करोड़ के ऐतिहासिक शिखर पर पहुँचा (2 अप्रैल 2026); 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी गई।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

विदेश मंत्रालय

जी-20 से वैक्सीन मैत्री तक — विश्वमित्र भारत



- 1 9 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली जी-20 घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ और अफ्रीकी संघ जी-20 का स्थायी सदस्य बना।
- 2 अगस्त 2026 तक 36 देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च या प्रमुख राजकीय सम्मान दिए, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सर्वाधिक है।
- 3 ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन, लगभग 22,500), कावेरी (सूडान, 3,862), अजय (इजराइल, लगभग 1,300), देवी शक्ति (अफ़ग़ानिस्तान, 669) और सिंधु (2025, लगभग 4,400) के अंतर्गत 30,000 से अधिक भारतीय संकटग्रस्त देशों से सुरक्षित लौटे; कोविड-काल के वंदे भारत मिशन में अगस्त 2020 तक ही 11 लाख से अधिक नागरिक स्वदेश लाए गए।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

वित्त मंत्रालय

जन धन से जीएसटी 2.0 तक



- 1 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई जन धन योजना के अंतर्गत 23 सितम्बर 2026 तक 59.37 करोड़ खाते खुले, जिनमें ₹3.18 लाख करोड़ जमा हैं; जन धन-आधार-मोबाइल के माध्यम से अब तक ₹51 लाख करोड़ से अधिक सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचे।
- 2 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ; 22 सितम्बर 2025 से जीएसटी 2.0 में 5% और 18% की दो मुख्य दरें प्रभावी हैं।
- 3 मुद्रा योजना में 27 मार्च 2026 तक 57.79 करोड़ ऋण (₹40.07 लाख करोड़) स्वीकृत हुए; जन सुरक्षा योजनाओं में 29 अप्रैल 2026 तक जीवन ज्योति बीमा के 27.43 करोड़ और सुरक्षा बीमा के 58.09 करोड़ नामांकन हुए।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

पीएम-किसान से ई-नाम तक

- 1 24 फरवरी 2019 से पीएम-किसान की 23 किस्तों में ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक सीधे किसानों के खातों में पहुँचे; 20 जून 2026 की 23वीं किस्त 9.44 करोड़ किसानों को मिली, जिनमें 2.18 करोड़ महिला किसान हैं।
- 2 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 2013-14 के ₹21,933 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹1,30,561 करोड़ हो गया — लगभग छह गुना; कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सहित मंत्रालय का कुल आवंटन ₹1,40,529 करोड़ है (बजट अनुमान 2026-27)।
- 3 अनाज उत्पादन 2013-14 के 2,650 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 3,765 लाख टन हो गया (तृतीय अग्रिम अनुमान, मई 2026)।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

सहकारिता मंत्रालय

6 जुलाई 2021 — पहली बार अलग मंत्रालय



- 1 6 जुलाई 2021 को सहकारिता के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बना; राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश में 8.4 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएँ और 32 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।
- 2 पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना में 79,630 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ शामिल हैं, जिनमें से 59,261 दिसम्बर 2025 तक साझा ईआरपी पर सक्रिय हो चुकी थीं; 15 फरवरी 2023 को हर पंचायत तक पहुँच के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का निर्णय हुआ।
- 3 11 जनवरी 2023 को निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज के लिए तीन राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ बनीं; 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी मिली।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

रेल मंत्रालय

वंदे भारत, चिनाब पुल, बुलेट ट्रेन



- 1 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत चली; जुलाई 2026 तक देश में 162 वंदे भारत सेवाएँ चल रही हैं, और 17 जनवरी 2026 को हावड़ा-गुवाहाटी पहली वंदे भारत स्लीपर रवाना हुई।
- 2 6 जून 2025 को विश्व का सबसे ऊँचा रेल आर्च — चिनाब पुल — राष्ट्र को समर्पित हुआ और कटरा-श्रीनगर वंदे भारत चली; 31 मई 2026 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकृत हो चुका है।
- 3 8 सितम्बर 2026 को वडोदरा में पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के अंतिम खंड राष्ट्र को समर्पित हुए और 2,843 किमी का समर्पित माल गलियारा पूरा हुआ; पूर्वी गलियारा 12 मार्च 2024 को पूरा हो चुका था।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

1.46 लाख किमी राष्ट्रीय राजमार्ग

- 1 राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 2014 के 91,287 किमी से बढ़कर दिसम्बर 2025 में 1,46,572 किमी हो गई; हाई-स्पीड कॉरिडोर 2014 के 550 किमी से बढ़कर दिसम्बर 2025 में 5,364 किमी हो गए (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)।
- 2 12 फरवरी 2023 को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला 246 किमी खंड और 11 मार्च 2024 को द्वारका एक्सप्रेसवे लोकार्पित हुए।
- 3 3 अक्टूबर 2020 को 9.02 किमी की अटल सुरंग और 9 मार्च 2024 को सेला सुरंग खुलीं; 9 जून 2026 को 13.15 किमी की जोजिला सुरंग में अंतिम ब्रेकथ्रू हुआ।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

166 हवाई अड्डे, उड़ान से आम आदमी तक

- 1 देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर सितम्बर 2026 में 166 हो गई; अक्टूबर 2016 से उड़ान योजना क्षेत्रीय उड़ानों को आम आदमी तक ले गई।
- 2 24 सितम्बर 2018 को पाक्योंग देश का 100वाँ और सिक्किम का पहला हवाई अड्डा बना; पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे 2014 के 9 से बढ़कर 2026 में 17 हो गए।
- 3 कुशीनगर (2021), मोपा (2022), देवघर (2022), अयोध्या (2023), नवी मुम्बई (2025) और नोएडा-जेवर (28 मार्च 2026) सहित नए हवाई अड्डे इसी अवधि में बने।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

जल शक्ति मंत्रालय

हर घर जल — लगभग 16 करोड़ नल कनेक्शन

- 1 15 अगस्त 2019 को शुरू हुए जल जीवन मिशन से अगस्त 2026 तक 15.91 करोड़ (82%) ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँचा, जबकि 2019 में यह संख्या 3.23 करोड़ (17%) थी।
- 2 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बने (सितम्बर 2026); 2014 में घोषित नमामि गंगे के ₹20,000 करोड़ के कार्यक्रम को 13 मई 2015 को मंजूरी मिली।
- 3 मई 2019 में जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता को एक छत के नीचे लाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

आयुष्मान भारत — विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना

- 1 23 सितम्बर 2018 को राँची से शुरू आयुष्मान भारत के लाभार्थी 60 करोड़ के पार हैं (सितम्बर 2026) और 30 जून 2026 तक ₹1.92 लाख करोड़ की 12.69 करोड़ निःशुल्क अस्पताल-भर्तियाँ अधिकृत हुईं; 29 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वय वंदना कार्ड से ₹5 लाख का कवर मिलता है।
- 2 एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई; 20,149 जन औषधि केंद्रों पर दवाएँ बाज़ार से 50–80% सस्ती मिलती हैं (30 जून 2026 तक)।
- 3 कोविड-19 में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला, जिसमें स्वदेशी टीकों सहित 220 करोड़ से अधिक खुराकें लगीं; 28 फरवरी 2026 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें सितम्बर 2026 तक 80 लाख से अधिक टीके लगे।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

आयुष मंत्रालय

9 नवम्बर 2014 — योग से WHO केंद्र तक



- 1 9 नवम्बर 2014 को आयुष मंत्रालय बना, जिससे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी को वैश्विक पहचान मिली।
- 2 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया; 2025 में विशाखापत्तनम में 3,00,105 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े योग सत्र का गिनीज़ रिकॉर्ड बना।
- 3 19 अप्रैल 2022 को जामनगर में WHO के वैश्विक पारम्परिक चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखी गई, जिसके लिए भारत ने 25 करोड़ डॉलर का सहयोग दिया; 13 नवम्बर 2020 को आईटीआरए जामनगर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

शिक्षा मंत्रालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020



- 1 29 जुलाई 2020 को 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकृत हुई, जिसने मातृभाषा में शिक्षा, कौशल और बहु-विषयक पढ़ाई को केंद्र में रखा।
- 2 परीक्षा पे चर्चा 2025 में 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज़ रिकॉर्ड बना और 2026 में पंजीकरण 4.5 करोड़ से अधिक हुए; नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खुलीं।
- 3 7 सितम्बर 2022 को स्वीकृत पीएम श्री योजना में 14,500 स्कूलों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है; 19 नवम्बर 2022 से काशी तमिल संगमम के चार संस्करण हो चुके हैं।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

मेट्रो 29 शहरों में, 4 करोड़ से अधिक घर



- 1 पीएम आवास योजना के शहरी और ग्रामीण घटकों से 2014 से 2024 के बीच 4.21 करोड़ पक्के घर बने (मंत्रिमंडल, 10 जून 2024), और इसी निर्णय से 3 करोड़ और घरों की सहायता स्वीकृत हुई।
- 2 मेट्रो नेटवर्क 2014 के 5 शहरों में 248 किमी से बढ़कर 26 मार्च 2026 तक 29 शहरों में 1,143 किमी (नमो भारत सहित) हो गया — विश्व का तीसरा सबसे बड़ा; 6 मार्च 2024 को कोलकाता में देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो चली।
- 3 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और पीएम आवास (शहरी) एक साथ शुरू हुए; जून 2020 से पीएम स्वनिधि के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को 1.12 करोड़ से अधिक ऋण (₹17,800 करोड़) मिले (मई 2026)।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

ग्रामीण विकास मंत्रालय

3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी

- 1 दीनदयाल अंत्योदय योजना के 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ जुड़ी हैं; 3.01 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं (फरवरी 2026) और 2029-30 तक 6 करोड़ का लक्ष्य है।
- 2 पीएम आवास योजना-ग्रामीण में 2.95 करोड़ घर पूरे हुए (फरवरी 2026); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अकेले पूर्वोत्तर में 46,290 किमी से अधिक सड़कें बनीं।
- 3 25 सितम्बर 2014 को शुरू दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण देती है।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

उज्ज्वला — 10.5 करोड़ से अधिक कनेक्शन



- 1 1 मई 2016 को बलिया से शुरू उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सितम्बर 2026 तक 10.57 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए।
- 2 जून 2022 में पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पाँच माह पहले पूरा हुआ।
- 3 7 फरवरी 2016 को 1.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष क्षमता की पारादीप रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित हुई; शहरी गैस वितरण नेटवर्क का देशव्यापी विस्तार हुआ।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

विद्युत मंत्रालय

हर गाँव, हर घर बिजली

- 1 28 अप्रैल 2018 को देश के हर गाँव तक बिजली पहुँच गई; 25 सितम्बर 2017 से सौभाग्य योजना ने 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए।
- 2 उजाला योजना के अंतर्गत लगभग 37 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित हुए, जिससे बिजली के बिल घटे।
- 3 3 फरवरी 2019 को लद्दाख राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा; पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में शत-प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण पूरा हुआ।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

168 GW सौर क्षमता



- 1 सौर क्षमता 31 अगस्त 2026 तक 168 गीगावाट और कुल गैर-जीवाश्म क्षमता 304 गीगावाट पहुँची; पंचामृत संकल्प के अनुसार 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य है।
- 2 13 फरवरी 2024 को घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (₹75,021 करोड़) का लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर है।
- 3 4 जनवरी 2023 को ₹19,744 करोड़ के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिली; अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डिजिटल इंडिया — UPI, आधार, सेमीकंडक्टर



- 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया शुरू हुआ; 2025-26 में यूपीआई पर ₹314 लाख करोड़ मूल्य के 24,162 करोड़ लेनदेन हुए और भारत रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान में विश्व में पहले स्थान पर है।
- 2 डिजिलॉकर के 70 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूजर हैं (सितम्बर 2026); 4 जुलाई 2022 को गांधीनगर से शुरू भाषिणी भारतीय भाषाओं में एआई अनुवाद का राष्ट्रीय मंच है।
- 3 भारत सेमीकंडक्टर मिशन में लगभग ₹1.64 लाख करोड़ के 12 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं (मई 2026), जिनमें धोलेरा में देश का पहला फैब शामिल है; 2 सितम्बर 2025 को पहला स्वदेशी 32-बिट चिप "विक्रम" प्रधानमंत्री को भेंट किया गया।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

संचार मंत्रालय

5G — 99.9% ज़िलों तक

- 1 अक्टूबर 2022 को 5जी सेवाएँ शुरू हुईं और आज 99.9% ज़िलों में उपलब्ध हैं (दिसम्बर 2025); भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5जी बाज़ार है।
- 3 जनवरी 2024 को कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों तक ₹1,072 करोड़ का समुद्री ऑप्टिकल फाइबर राष्ट्र को समर्पित हुआ; 10 अगस्त 2020 को चेन्नई-अंडमान समुद्री केबल शुरू हुई थी।
- 3 नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में 9,100 से अधिक मोबाइल टावर लगे (10,734 स्वीकृत) और 5,700 से अधिक डाकघर खुले (2025); 4 जनवरी 2022 को मणिपुर में 2,387 टावर राष्ट्र को समर्पित हुए।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

मेक इन इंडिया से पीएलआई तक

- 1 25 सितम्बर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई; 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ₹1.97 लाख करोड़ की पीएलआई योजनाएँ लागू हैं (बजट 2021-22 में घोषित)।
- 2 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 2.35 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं (जून 2026) और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
- 3 यूएई (2022), ऑस्ट्रेलिया (2022) और ईएफटीए (2025 से प्रभावी) के साथ व्यापार समझौते हुए; 9 अगस्त 2016 से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर कुल खरीद ₹20 लाख करोड़ के पार है (अगस्त 2026)।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

स्किल इंडिया — 1.6 करोड़ से अधिक युवा



- 1 9 नवम्बर 2014 को नया मंत्रालय बना और 15 जुलाई 2015 से स्किल इंडिया मिशन शुरू हुआ; पीएम कौशल विकास योजना से 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिला (जुलाई 2025)।
- 2 17 सितम्बर 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना के 18 पारम्परिक व्यवसायों के कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण यह मंत्रालय संभालता है; सितम्बर 2026 तक 30 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हुए।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से मिशन शक्ति तक

- 1 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ; उसी दिन शुरू सुकन्या समृद्धि योजना में 4.53 करोड़ खाते खुल चुके हैं (जनवरी 2026)।
- 2 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से पोषण अभियान और 2021-22 से मिशन शक्ति शुरू हुए, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की समग्र योजना है।
- 3 28 सितम्बर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी; 2017 के मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम से सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 से बढ़कर 26 सप्ताह हुआ।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सुगम्य भारत से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तक



- 1 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए; 3 दिसम्बर 2015 से सुगम्य भारत अभियान चल रहा है।
- 2 अगस्त 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला; 14 जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण लागू है।
- 3 5 अप्रैल 2016 से स्टैंड-अप इंडिया अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण देती है।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय गौरव दिवस से पीएम जनमन तक



- 1 15 नवम्बर 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है; 15 नवम्बर 2024 से उनका 150वाँ जयंती वर्ष मनाया गया।
- 2 नवम्बर 2023 में स्वीकृत पीएम जनमन (₹24,104 करोड़) 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक पक्के घर, सड़क, जल और स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचा रहा है; सितम्बर 2024 में स्वीकृत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹79,156 करोड़) 63,000 से अधिक गाँवों तक पहुँचेगा।
- 3 देश में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत हैं, जिनमें से पहला 15 नवम्बर 2021 को राँची में खुला।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

संस्कृति मंत्रालय

15 नए यूनेस्को स्थल, 600 से अधिक कलाकृतियाँ वापस

- 1 2014 से 15 भारतीय स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जुड़े और कुल संख्या 45 हुई; 25 जुलाई 2026 को सारनाथ इस सूची में शामिल हुआ।
- 2 2014 से 600 से अधिक प्राचीन कलाकृतियाँ स्वदेश लौटीं, जिनमें सितम्बर 2024 में अमेरिका से एक साथ लौटी 297 कलाकृतियाँ शामिल हैं।
- 3 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय खुला; 28 मई 2023 को नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित हुआ; नॉर्थ और साउथ ब्लॉक युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलेंगे (मंत्रिमंडल, फरवरी 2026)।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

पर्यटन मंत्रालय

स्वदेश दर्शन और प्रसाद — तीर्थ से पर्यटन तक

- 1 2014-15 से स्वदेश दर्शन के थीम-सर्किट और प्रसाद योजना से देश भर के तीर्थ-स्थलों का विकास हुआ।
- 2 जम्मू-कश्मीर में 2024 में 2.35 करोड़ से अधिक पर्यटक आए; जनवरी 2024 की प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा ने द्वीप पर्यटन को नई पहचान दी।
- 3 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से विश्व का सबसे लम्बा नदी क्रूज़ गंगा विलास रवाना हुआ।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

खेलो इंडिया से ओलंपिक 2036 तक

- 1 2017-18 से खेलो इंडिया और 29 अगस्त 2019 से फिट इंडिया आंदोलन चल रहे हैं; 31 जुलाई 2026 को 2026-31 के लिए ₹36,441 करोड़ की संशोधित खेलो इंडिया योजना मंजूर हुई।
- 2 एशियाई खेल 2023 में 107 पदक और पैरालंपिक 2024 में 29 पदक — दोनों भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे; टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक मिले।
- 3 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत (MY Bharat) की स्थापना हुई; 28 जनवरी 2025 को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हुए और 26 नवम्बर 2025 को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी अहमदाबाद को मिली।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

अंतरिक्ष विभाग

चंद्रयान-3 — दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा

- 1 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा और लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया; 2 सितम्बर 2023 को सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य-एल1 रवाना हुआ।
- 2 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वाँ प्रक्षेपण हुआ; 30 जुलाई 2025 को नासा-इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार कक्षा में स्थापित हुआ।
- 3 जून 2020 में इन-स्पेस के गठन से अंतरिक्ष क्षेत्र निजी उद्यमों के लिए खुला; 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय यात्री भेजने का लक्ष्य है।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

क्वांटम मिशन, अनुसंधान एनआरएफ

- 1 19 अप्रैल 2023 को ₹6,003 करोड़ के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी मिली; अगस्त 2023 में संसद ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम पारित किया।
- 2 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 के 81वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान पर पहुँचा; 16 जून 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ₹4,077 करोड़ के डीप ओशन मिशन को मंजूरी मिली।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

विड़िंजम से वाढवण तक



- 1 2 मई 2025 को देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विड़िंजम (₹8,800 करोड़) राष्ट्र को समर्पित हुआ।
- 2 30 अगस्त 2024 को ₹76,220 करोड़ के वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखी गई — ऑल-वेदर ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट मेजर पोर्ट, जो विश्व के दस सबसे बड़े बंदरगाहों में होगा; 25 मार्च 2015 को सागरमाला कार्यक्रम स्वीकृत हुआ था।
- 3 9 अक्टूबर 2024 को लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी मिली; 25 अप्रैल 2023 को कोच्चि में देश की पहली वॉटर मेट्रो चली।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

2019 में नया मंत्रालय — समुद्र से समृद्धि

- 1 मछली उत्पादन 2013-14 के 95 लाख टन से दोगुना से अधिक बढ़कर 2024-25 में 198 लाख टन हुआ; ₹20,050 करोड़ की पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (2020-25) इस क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है।
- 2 2014 से 2,661 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत से मुक्त होकर लौटे (1 जुलाई 2026)।
- 3 बजट 2018-19 से मछुआरों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली; 2019 में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग मंत्रालय बना।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज



- 1 मार्च 2020 से शुरू पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है, जिसे 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
- 2 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से प्रवासी देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं — अब तक 201 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन (फरवरी 2026); 2023 से भारत ब्रांड आटा, चावल और दाल उपलब्ध हैं।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

ई-श्रम — असंगठित कामगारों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस

- 1 26 अगस्त 2021 को शुरू ई-श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ असंगठित कामगार पंजीकृत हैं (अगस्त 2026); 5 मार्च 2019 से पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना चल रही है।
- 2 2017 के मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम से सवैतनिक मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह हुआ; 21 नवम्बर 2025 से 29 श्रम कानूनों की जगह चार श्रम संहिताएँ लागू हैं।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

अष्ट लक्ष्मी — प्रधानमंत्री 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर में

- 1 प्रधानमंत्री 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर गए (जून 2026); क्षेत्र में 4,170 किमी से अधिक रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ और पाँच राज्यों — अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम — का रेल नेटवर्क शत-प्रतिशत विद्युतीकृत है।
- 2 पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे 2014 के 9 से बढ़कर 17 हुए; 24 सितम्बर 2018 को सिक्किम का पहला हवाई अड्डा पाक्योंग और 19 नवम्बर 2022 को ईटानगर का डोनी पोलो हवाई अड्डा खुला; 29 नवम्बर 2014 को मेघालय की पहली यात्री ट्रेन चली और 13 सितम्बर 2025 को आइज़ोल रेल से जुड़ा।
- 3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ₹47,270 करोड़ से अधिक की लागत से 46,290 किमी से अधिक ग्रामीण सड़कें बनीं; 4 फरवरी 2024 को माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास हुआ।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

वोकल फॉर लोकल — खादी की रिकॉर्ड बिक्री

- 1 खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.87 लाख करोड़ पहुँची, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार मिला, जिनमें 80% महिलाएँ हैं (मई 2026)।
- 2 8 अप्रैल 2015 से मुद्रा योजना और 17 सितम्बर 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना छोटे उद्यमियों और कारीगरों को बिना गारंटी ऋण देती हैं; पीएम विश्वकर्मा में सितम्बर 2026 तक 30 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हुए।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

विधि एवं न्याय मंत्रालय

तीन तलाक कानून से एक देश एक चुनाव तक

- 1 31 जुलाई 2019 को तीन तलाक के विरुद्ध कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली; मई 2014 से अब तक 1,600 से अधिक अप्रचलित कानून निरस्त किए गए (दिसम्बर 2025)।
- 2 17 दिसम्बर 2024 को एक देश, एक चुनाव के लिए संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है।
- 3 16 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रवृत्त करने की अधिसूचना जारी हुई, जिसका आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन के साथ लागू होगा।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

चीता की वापसी, 891 सिंह, 2070 नेट-ज़ीरो

- 1 17 सितम्बर 2022 को कुनो में 70 वर्ष बाद चीतों की वापसी हुई और सितम्बर 2026 में देश में 56 चीते हैं (18 सितम्बर 2026, कुनो में चार शावकों के जन्म के बाद); 2025 की 16वीं गणना में 891 एशियाई सिंह और 2022 की गणना में 3,682 बाघ दर्ज हुए।
- 2 1 नवम्बर 2021 को ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने 2070 तक नेट-ज़ीरो का पंचामृत संकल्प रखा; 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ शुरू हुआ।
- 3 5 जून 2024 से "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान चल रहा है।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

कोयला एवं खान मंत्रालय

1 अरब टन कोयला

- 1 मार्च 2025 में देश का कोयला उत्पादन पहली बार एक वर्ष में 1 अरब टन के पार गया (2024-25 में 104.7 करोड़ टन); 18 जून 2020 से वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी शुरू हुई।
- 2 29 जनवरी 2025 को ₹16,300 करोड़ के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी मिली।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

इस्पात, भारी उद्योग एवं वस्त्र मंत्रालय

नगरनार से पीएम मित्र तक



- 1 3 अक्टूबर 2023 को बस्तर में ₹23,800 करोड़ से अधिक की लागत का एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित हुआ।
- 2 11 सितम्बर 2024 को स्वीकृत ₹10,900 करोड़ की पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू है; 17 मार्च 2023 को सात पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों के स्थल घोषित हुए।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

पंचायती राज मंत्रालय

स्वामित्व — गाँव की संपत्ति के कार्ड

- 1 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना और ई-ग्राम स्वराज शुरू हुए; ड्रोन सर्वे से 3.10 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार हुए, जिनमें 2.65 करोड़ वितरित हो चुके हैं (मार्च 2026)।
- 2 2001 में मुख्यमंत्री काल में शुरू गुजरात की समरस ग्राम योजना ने सर्वसम्मति से पंचायत चुनने की परम्परा को प्रोत्साहन दिया।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

नीति आयोग / प्रधानमंत्री कार्यालय

योजना आयोग से नीति आयोग तक



- 1 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना; 25 मार्च 2015 से प्रधानमंत्री प्रगति मंच पर बड़ी परियोजनाओं की सीधी निगरानी करते हैं।
- 2 जनवरी 2018 से 112 आकांक्षी ज़िलों का कार्यक्रम चल रहा है; 2 सितम्बर 2020 को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी मिली।
- 3 नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ (लगभग 25 करोड़) लोग गरीबी से बाहर आए।

— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मन की बात से वेक्स तक

- 1 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का प्रसारण हो रहा है — 27 सितम्बर 2026 को 138वीं कड़ी प्रसारित हुई; 30 अप्रैल 2023 की 100वीं कड़ी का सीधा प्रसारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी हुआ।
- 2 1 मई 2025 को मुम्बई में पहला विश्व ऑडियो-विज़ुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स) हुआ।



— मंत्रालय · हर मंत्रालय, अपना हस्ताक्षर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

हज से वक्फ सुधार तक

- 1 2018 से महिलाएँ बिना मेहरम हज पर जा सकती हैं; 2023 में 4,000 से अधिक महिलाएँ इस सुविधा से हज पर गईं।
- 2 8 अप्रैल 2025 से वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू हुआ।

